राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर सरकार को घेरा

विपक्ष ने लोकतंत्र और वोट अधिकार पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 02 दिसम्बर. संसद भवन परिसर में मंगलवार को विपक्षी दलों ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया.

इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, द्रमुक के टी आर बालू सहित दोनों सदनों के कई प्रमुख सांसद शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की. प्रियंका गांधी ने भी संचार साथी ऐप को जासूसी का माध्यम बताते हुए सरकार पर कड़ा हमला किया. वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को कुछ नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुराने मामलों में नई प्राथमिकी दर्ज कराई गई. विपक्ष ने एसआईआर और लोकतंत्र पर

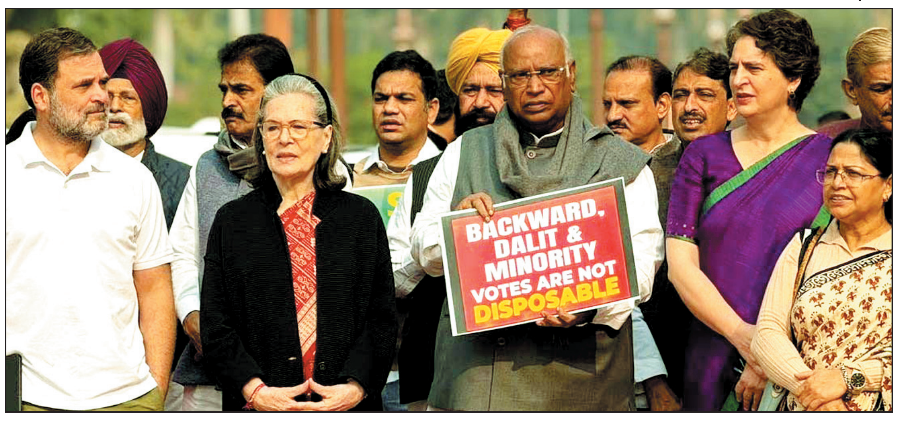

बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई. भवन के मकर द्वार के बाहर विपक्षी दलों ने एसआईआर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे कई प्रमुख सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उपनेता गौरव गोगोई, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं ने भी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की. विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले यहां भवन परिसर के मकर द्वार के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया.

प्रियंका ने संचार साथी ऐप पर हमला बोला

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को हास्यास्पद बताते हुए आरोप लगाया कि यह जासूसी ऐप है जिसके जरिए सरकार हर मोबाइल पर नजर रखना चाहती है. प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने संबंधी सवाल पर कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और यह हास्यास्पद है. नागरिकों को निजता का अधिकार है और सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए.

खरगे नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जब भाजपा सरकार को कुछ नही मिला तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले में नयी प्राथमिकी दायर की गई है. श्री खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा 12 साल बाद अचानक गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई. यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया.

बम की धमकी के बाद विमान डायवर्ट, नहीं मिला विस्फोटक

मुंबई, 02 दिसंबर. कुवैत से हैदराबाद आ रहे इंडिगो के एक विमान को मंगलवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर उस समय आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी जब अधिकारियों को बम होने की गंभीर धमकी मिली.

सुरक्षाकर्मी विमान के उतरते ही तुरंत उसे अलग स्थान पर ले गये और उसकी गहन जाँच की. विमान में बम होने की चेतावनी देने वाला यह संदेश ईमेल के जरिये भेजा गया था, जिसके बाद हैदराबाद और मुंबई दोनों हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया. विमान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला और कड़ी जांच के बाद इस धमकी को

महज अफवाह घोषित कर दिया गया. इंडिगो ने आज एक बयान जारी कर पुष्टि की कि कुवैत और हैदराबाद के बीच उड़ान भरने वाली उसकी उड़ान 6ई1234 को सुरक्षा संबंधी धमकी मिलने के बाद दो दिसंबर, 2025 को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया था. एयरलाइन ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि विमान को आगे की यात्रा के लिए मंजूरी देने से पहले स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा जाँच करने में पूरा सहयोग कर रही है.

नेहरू बाबरी निर्माण चाहते थे : राजनाथ

नेहरू-पटेल विवाद पर रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

सडली, 02 दिसंबर. गुजरात के सडली गांव में आयोजित 'यूनिटी मार्च' कार्यक्रम में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा दावा किया जिसने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसे सख्ती से रोक दिया. राजनाथ सिंह के अनुसार, यह मतभेद सिर्फ एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं था,

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 'यूनिटी मार्च' कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दावा किया जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी. उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करने का सुझाव दिया था, जिसे तत्कालीन गृह एवं उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया. राजनाथ के अनुसार, यह घटना उस दौर में दोनों नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण में मौजूद गहरे मतभेदों को दर्शाती है.

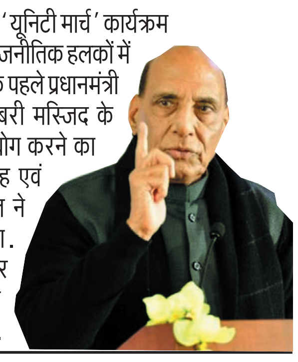

बल्कि उस दौर की नेतृत्व शैली, राजनीतिक प्राथमिकताओं और 'धर्मनिरपेक्षता की अलग-अलग परिभाषाओं' का प्रतीक था. कार्यक्रम के दौरान सिंह ने नेहरू-पटेल संबंधों से जुड़े कई दावे किए—चाहे वह सोमनाथ मंदिर निर्माण की कहानी हो, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो या फिर राष्ट्रीय स्मारकों के प्रति नेहरू का रुख. राजनाथ ने कहा कि सालों तक पटेल की विरासत को दबाने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उसका सम्मान बहाल किया. जैसे ही उनके ये बयान सामने आए, देशभर में राजनीतिक चर्चाएं तेज़ हो गई.

राशि अली की कस्टडी बढ़ी

लाल किला ब्लास्ट केस: एनआईए कोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. दिल्ली ब्लास्ट 2025 स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट केस में आमिर राशिद अली की कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है. उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया.

पुलिस के अनुसार, पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था. उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट रूम में आमिर को पेश कर तर्क दिया था कि आरोपी से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सह-साजिशकर्ताओं की पहचान को

लेकर विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत आवश्यक है. एनआईए ने दलील दी थी कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत को मंजूरी दे दी. अदालत परिसर में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात थे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण पुलिस की टीमें तैनात थीं.

प्रदूषण के लिए किसान अकेले दोषी नहीं

न्यायालय ने केंद्र को प्रदूषण रोकथाम रिपोर्ट देने को कहा

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट के लिए किसानों को अकेला जिम्मेदार ठहराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सवाल उठाया.

न्यायालय ने कहा कि पराली जलाना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी मौजूद था, जबकि राजधानी में उस समय असाधारण रूप से साफ आसमान देखा गया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर लंबे समय से लंबित एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि

पराली जलाने के आसपास की कहानी को एक राजनीतिक मुद्दा या अहंकार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. पीठ ने दोहराया कि दिल्ली की जहरीली हवा के कई स्रोत हैं. मुख्य न्यायाधीश ने प्रदूषण के प्राथमिक योगदानकर्ताओं की पहचान करने वाले वैज्ञानिक विश्लेषणों पर स्पष्टता की मांग की. उन्होंने कहा कि जहाँ पराली जलाने को लगातार उजागर किया जाता है, वहीं उन लोगों पर बोझ डालना गलत होगा जिनका न्यायालय में शायद ही कोई प्रतिनिधित्व हो.

सरकार से कई सवाल

उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई थी. अब असली सवाल यह है कि उस समय साफ नीला आसमान क्यों दिखाई दे रहा था. न्यायालय ने कहा कि किसान अक्सर अपनी आजीविका की रक्षा के लिए पराली जलाते हैं और उन्हें अनुचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पराली जलाने के अलावा अन्य सभी प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी उपायों पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे. न्यायालय ने सरकार से पूछा कि क्या उसकी कार्य योजनाओं ने ठोस सुधार किए हैं? उन योजनाओं की फिर से जाँच क्यों नहीं की जा सकती है?

एक नजर में

पोलैंड को मिली अब्राम्स टैंकों की नई खेप

वारसॉ, 02 दिसंबर. पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल बेजदा ने बताया कि सेना को अमेरिका के 32 एम1ए2 अब्राम्स टैंक की खेप मिलने से रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. पावेल बेजदा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह नवीनतम अब्राम्स टैंकों की चौथी खेप है. वर्तमान में, 32 एम1ए2 टैंक पोलिश बंदरगाह पर उतारे जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि ये टैंक पोलिश सशस्त्र समूह के संयंत्र में संशोधित किये जाने के बाद सेवा में शामिल किए जाएंगे. बता दें 2022 में, पोलैंड और अमेरिका ने संबंधित उपकरण, रसद व एक प्रशिक्षण पैकेज के साथ 250 एम1ए2 अब्राम्स टैंकों की आपूर्ति के लिए 4.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे.

न्यायालय ने रिलायंस की याचिका की खारिज

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की ओर से सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) की आदेश को चुनौती देने वाली दायर याचिका को खारिज कर दी. वहीं उच्चतम न्यायालय कंपनी पर जुर्माने को बरकरार रखा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आरआईएल और उसके अनुपालन अधिकारियों सविता पारेख और के. सेथुरमन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, हम संतुष्ट हैं कि हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है. 2015 के विनियमों के उल्लंघन के संबंध में सेबी के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है. सेबी और सैट द्वारा निपटाए गए मुद्दे पर्याप्त रूप से तथ्यात्मक हैं और कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाते हैं.

अग्रिम पंक्ति के प्रमुख शहरों पर रूस का नियंत्रण

मॉस्को, 02 दिसंबर. रूसी सेना ने डोनबास में क्रास्नोआर्मेस्क और खारकोव क्षेत्र में वोल्चांस्क सहित कई प्रमुख अग्रिम पंक्ति के शहरों पर नियंत्रण कर लिया है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 30 नवंबर को एक कमांड पोस्ट के दौरे के दौरान यह जानकारी दी . पुतिन को बताया कि जापोराजिया क्षेत्र में गुलयायपोल को भी नियंत्रण में लेने का अभियान शुरू हो गया है. राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति ने आगामी सर्दियों के दौरान युद्ध अभियानों के लिए सैनिकों को सभी आवश्यक चीज़ प्रदान करने के लिए निर्देश दिये हैं.

संचार ऐप पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता पर सीधा हमला

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. देश में डिजिटल निजता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. मोबाइल निर्माताओं को सभी नए और पुराने फोन पर 'संचार साथी' ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के सरकारी निर्देश के बाद राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है.

आम आदमी पार्टी ने इस आदेश पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता पर सीधा हमला बताया है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया

के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जहां बिना उपयोगकर्ता की अनुमति किसी सरकारी ऐप को अनिवार्य रूप से डिवाइस में डालने का आदेश दिया गया हो. उन्होंने दावा किया कि जारी नोटिफिकेशन में न तो नागरिकों से सहमति लेने की बात कही गई है और न ही ऐप को हटाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है.

केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिसकी मिसाल किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती. उनके मुताबिक, किसी भी ऐप को उपयोगकर्ता की सहमति के बिना फोन में डालना और उसे हटाने का विकल्प न देना नागरिक अधिकारों को कमजोर करने जैसा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जारी नोटिफिकेशन में नागरिकों के अधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं है. न यह बताया गया है कि ऐप किस उद्देश्य से इस्तेमाल होगा, न यह कि इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा.

आज का इतिहास

- 1776 मराठा साम्राज्य के महाराजा यशवंतराव होलकर का जन्म।
- 1796 बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बनाया गया।
- 1829 वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई।
- 1882 आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म।
- 1884 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म।

इमरान से मिलीं बहन,कहा- उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रहे

इमरान खान के स्वास्थ्य की जांच को मिली मंजूरी

इस्लामाबाद, 02 दिसंबर. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उज्मा खान ने मंगलवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की.

जेल से बाहर आकर उज्मा ने आरोप लगाया कि भाई इमरान पूरी तरह ठीक हैं. दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. बता दें महीनों से इमरान खान से परिवार की किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया जा रहा था. उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. कहीं वे गंभीर रूप से बीमार तो नहीं, कहीं जेल प्रशासन कोई जानकारी छिपा तो नहीं रहा. यहां तक कि कुछ आलोचकों ने इमरान खान की जीवित स्थिति पर भी संदेह जताना शुरू कर दिया था. ऐसे माहौल में सरकार द्वारा अचानक मुलाकात की मंजूरी देना कई संकेत छोड़ता है. इमरान की बहनें लंबे समय से आदियाला जेल के बाहर विरोध कर रही थीं. हजारों पीटीआई समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया.

रावलपिंडी-इस्लामाबाद में धारा 144 लागू

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में बढ़ती अनिश्चितता के बीच पीटीआई के समर्थकों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनायी है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बढ़ते असंतोष की आशंकाओं के मद्देनजर रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. रिपोर्टों से पता चला है कि इमरान खान की तीन बहनें और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने की अनुमति देने का दबाव बनाने के लिए अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं. पार्टी ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय और अदियाला जेल के बाहर नये सिरे से विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

जज का मोबाइल चोरी, खाते से निकले लाखों रु.

रांची, 02 दिसंबर. झारखंड की राजधानी रांची में एक हैरान करने वाली खबर आयी ,जहां चोरों ने जज को निशाना बनाया ओर भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी कर ली. जज खूंटी जिले में पदस्थापित हैं. वहीं चोरी के कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 2.88 लाख रुपये की बड़ी राशि डिजिटल माध्यम से निकाल ली गई. इस संबंध में जज ने जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जज धुर्वा के सेक्टर-2 बाजार में सब्जी खरीदने गए थे. इसी दौरान किसी अज्ञात अपराधी ने बड़ी चतुराई से उनका मोबाइल फोन चुरा लिया.

आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेगा रूस

कल भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन

नई दिल्ली, 02 दिसंबर (वार्ता) रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा.

पुतिन की चार दिसंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय भारत यात्रा से पेस्कोव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया. यहां उन्होंने कहा कि हमारा मानना है आतंकवाद का मुकाबला करने का एक मात्र

तरीका अंतरराष्ट्रीय सहयोग है. दुर्भाग्य से यूरोपीय देशों के साथ इस समय हमारे जिस प्रकार के रिश्ते हैं, वे हमारे लिए उस संभावना को सीमित करते हैं. भारत के साथ मिलकर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखेंगे.

यदि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई करता है तो क्या रूस उसका समर्थन करेगा. रूसी अधिकारी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, उसका कोई भी स्रोत हो, उनका देश उसकी पुरजोर निंदा करता है. उन्होंने कहा हमारे देश ने आतंकवाद का दंश काफी झेला है और हम इसके दर्द को समझते हैं. हमें मालूम है कि भारत ने अनेक बार इस खतरे का सामना किया है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण देश है.

कर्नाटक राजनीति | हाईकमान के आदेश के बाद 4 दिन में दूसरी मुलाकात, सिद्धारमैया बोले-

हाईकमान कहेगा तो शिवकुमार बनेंगे सीएम

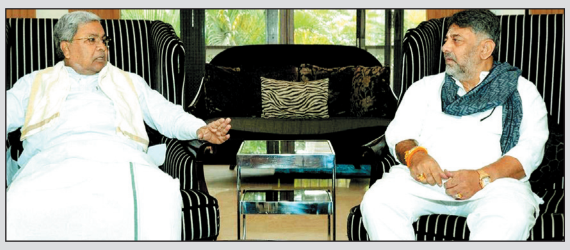

बेंगलुरु, 02 दिसंबर. कर्नाटक की सियासत में काफी समय से चल रही मुख्यमंत्री पद की खींचतान के बीच एक महत्वपूर्ण बात सामने निकलकर आ रही है.

वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जब कोई हाईकमान कहेगा तो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में कुछ नए संकेत देखने को मिल रहे हैं. सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, और दोनों नेता राज्य सरकार को मिलकर चला रहे हैं. मंगलवार सुबह सिद्धारमैया शिवकुमार के घर पहुंचे, जहां स्वागत डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने किया.

अभी हाल की हलचलें

बीजेपी ने शिवकुमार का वीडियो जारी कर तंज कसा-सीएम कुर्सी आउट ऑफ स्टॉक- 21 नवंबर को शिवकुमार ने कहा—सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

- 19 नवंबर को शिवकुमार ने संकेत दिए कि वे प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं
- 16 नवंबर को सिद्धारमैया ने खड़गे से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की

कांग्रेस सरकार के गठन के समय यह बात सामने आई थी कि सीएम पद के लिए 2.5-2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया था. 20 नवंबर को सिद्धारमैया की 2.5 साल की अवधि पूरी होने के बाद शिवकुमार खेमे के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे और नेतृत्व परिवर्तन की मांग की. दूसरी तरफ, सिद्धारमैया गुट इन दावों को लगातार खारिज करता रहा है. सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल चाहते हैं लेकिन शिवकुमार नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला चाहते हैं.

54वां ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कॉम्पिटिशन हुआ प्रारंभ

नागपुर, 02 दिसबंर. नागपुर में 54वां ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कॉम्पिटिशन, 02 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ.

54वां ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कॉम्पिटिशन 2025 (कोल और मेटल) सुबह 07:30 बजे डब्लूसीएल परेड ग्राउंड, माइंस रेस्क्यू स्टेशन (एमआरएस), नागपुर में शुरू हुआ, जिसे मॉयल लिमिटेड द्वारा गर्व से आयोजित किया गया. यह प्रतिष्ठित नेशनल लेवल का इवेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) के तहत आयोजित किया जा रहा है. उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि, राम अवतार मीणा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (वेस्टर्न जोन), डीजीएमएस, नागपुर और एन.पी. देवरी, डीएमएस और चीफ जज मौजूद थे. इस इवेंट में डीजीएमएस, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और मॉयल लिमिटेड के कई विशिष्ट अतिथियों और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रतिभागी सभी रेस्क्यू टीमों को शुभकामनाएं दीं. इस वार्षिक प्रतियोगिता का उद्देश्य, खान सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और बढ़ावा देना, आपातकालीन तैयारी को बढ़ाना और देश भर में कोल और मेटल माइनिंग सेक्टर की रेस्क्यू टीमों के बीच समन्वय और टीमवर्क को मजबूत करना है. अलग-अलग माइनिंग ऑर्गनाइजेशन की प्रतिभागी टीमें रेस्क्यू ड्रिल और टेक्निकल इवेंट में हिस्सा लेंगी.

मोदी सरकार सत्ता नहीं, सेवा की पर्याय रही है : अमित शाह

नईदिल्ली, 2 दिसंबर. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता नहीं, सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता के सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधानसेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं.

इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को 'सेवा तीर्थ' नाम दिया है. साथ ही, राजभवन और राज निवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है. यह सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित तथा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत

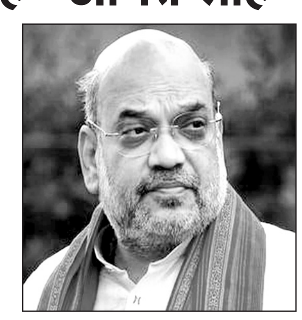

के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा में एक अहम पड़ाव है. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता नहीं, सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता के सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधानसेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं.